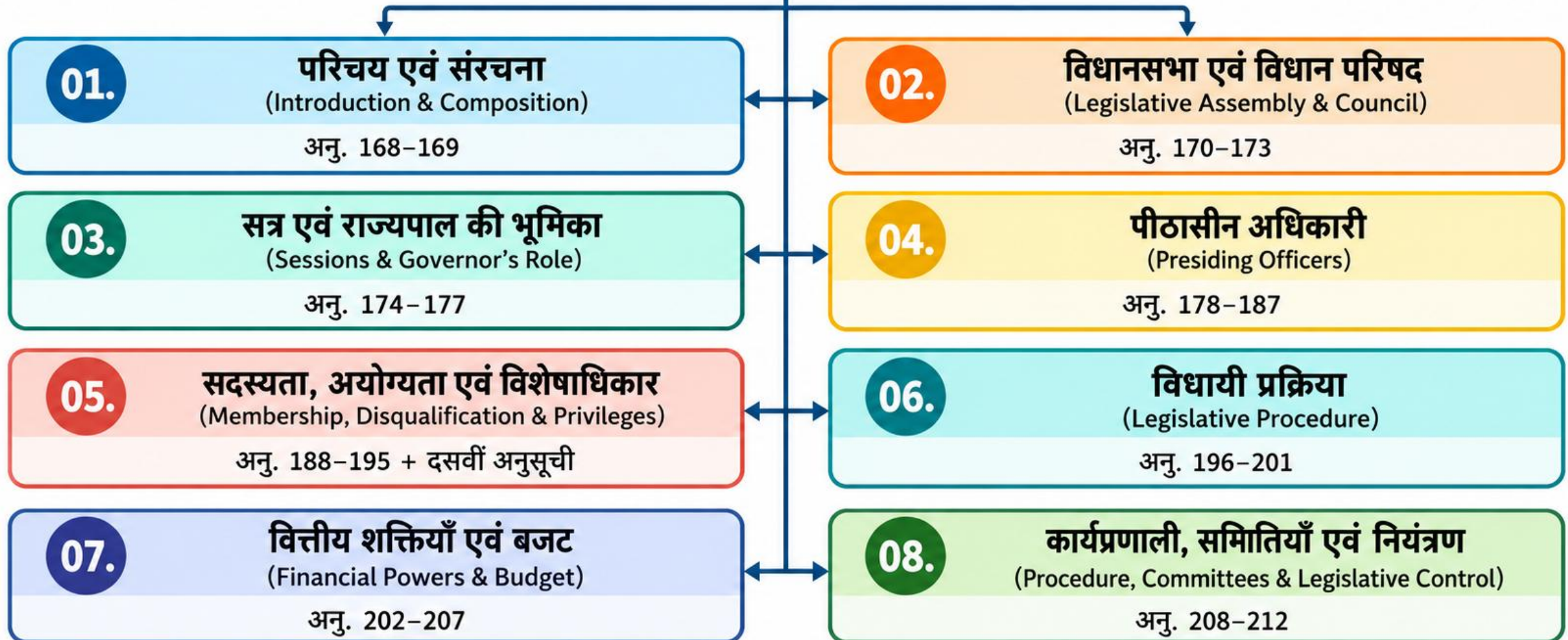


अध्याय 21 : राज्य की विधायिका (State Legislature)

भाग VI → 168 से 212



Chapter 21: State Legislature

PART VI → 168 - 212

01. Introduction & Composition

(Articles 168 – 169)



02.

Legislative Assembly & Legislative Council

(Articles 170 – 173)



03. Sessions & Governor's Role

(Articles 174 – 177)



04.

Presiding Officers

(Articles 178 – 187)



05. Membership, Disqualification & Privileges

(Articles 188 – 195 + Tenth Schedule)



06.

Legislative Procedure

(Articles 196 – 201)



07. Financial Powers & Budget

(Articles 202 – 207)



08.

Procedure, Committees & Legislative Control

(Articles 208 – 212)



अनुच्छेद 168 → राज्यों में विधानमंडलों का गठन (Constitution of Legislatures in States)



क्र.	विधान परिषद	परिषद सदस्य	विधानसभा सदस्य
1	आंध्र प्रदेश	58	175
2	तेलंगाना	40	119
3	उत्तर प्रदेश	100	403
4	बिहार	75	243
5	महाराष्ट्र	78	288
6	कर्नाटक	75	224

- केवल 3 केंद्रशासित प्रदेश में विधानसभा — दिल्ली (70), पुडुचेरी (30), जम्मू-कश्मीर (90)
- 7वें संशोधन, 1956 द्वारा म.प्र. में विधान परिषद का प्रावधान किया गया, — राष्ट्रपति की अधिसूचना आज तक जारी नहीं हुई,
- तमिलनाडु विधान परिषद अधिनियम, 2010 पारित हुआ पर लागू नहीं हुआ — 2011 में विधानसभा ने परिषद उन्मूलन का प्रस्ताव पारित।

MLA (Member of
Legislative Assembly)

MLC (Member of
Legislative Council)

Article 168 → Constitution of Legislatures in States

Organs of the Legislature

Governor

Legislative Council → 6 States

Legislative Assembly → all 28 States

No.	State	MLCs	MLAs
1	Andhra Pradesh	58	175
2	Telangana	40	119
3	Uttar Pradesh	100	403
4	Bihar	75	243
5	Maharashtra	78	288
6	Karnataka	75	224

- Only **3 UTs** have an Assembly: **Delhi** (70), **Puducherry** (30), **J&K** (90)
- The **7th Amendment, 1956** provided for a Council in M.P., but the **President's notification was never issued**
- The **Tamil Nadu Legislative Council Act, 2010** was passed but **never enforced**; in 2011 the Assembly voted to abolish the Council

*MLA (Member of
Legislative Assembly)*

*MLC (Member of
Legislative Council)*

अनुच्छेद 169 → विधान परिषदों के निर्माण और समाप्ति

- ❑ **शुरुआत (Initiative)** → विधान परिषद बनानी या समाप्त करना है, इसकी पहल स्वयं उस राज्य की **विधान सभा (Legislative Assembly)** ही कर सकती है।
 - ✓ राज्य विधानसभा को ऐसा प्रस्ताव विशेष बहुमत से पारित करना होता है।
 - ✓ सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का कम से कम दो-तिहाई
- ❑ **अंतिम शक्ति संसद के पास** → संसद कानून बनाकर उस राज्य में विधान परिषद का सृजन या समापन कर सकती है।
 - ✓ केवल साधारण बहुमत (Simple Majority)
 - ✓ संसद विधानसभा के संकल्प को मानने के लिए बाध्य नहीं
- ❑ अनुच्छेद 169 के तहत संसद द्वारा किया गया यह बदलाव, अनुच्छेद 368 के तहत 'संविधान संशोधन' नहीं माना जाता है।

1 शुरुआत (Initiative)

विधान परिषद बनानी या समाप्त करनी है, इसकी पहल स्वयं उस राज्य की **विधान सभा (Legislative Assembly)** ही कर सकती है।



2 राज्य विधानसभा में प्रस्ताव

राज्य विधानसभा को ऐसा प्रस्ताव **विशेष बहुमत** से पारित करना होता है।

विशेष बहुमत =

- सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत +
- उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का कम से कम दो-तिहाई।

3 अंतिम शक्ति संसद के पास

संसद कानून बनाकर उस राज्य में **विधान परिषद का सृजन या समापन** कर सकती है।

संसद में यह कानून केवल **साधारण बहुमत (Simple Majority)** से पारित होता है।

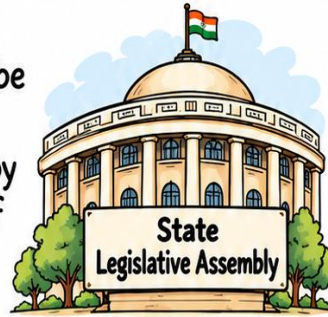


Article 169 → Creation and Abolition of Councils

- ❑ **Initiative** → only the **Legislative Assembly** of that State can start the creation or abolition of its Legislative Council
 - ✓ The State Assembly must pass the resolution by a **special majority**:
 - ✓ majority of total membership and at least two-thirds of the members present and voting
- ❑ **Final power lies with Parliament** → Parliament can create or abolish the Council in that State by law
 - ✓ Only a **simple majority** is needed
 - ✓ Parliament is **not bound** to act on the Assembly's resolution
- ❑ Such a law under Article 169 is **not deemed an amendment** of the Constitution under Article 368

1 Initiative

If a Legislative Council is to be created or abolished, the initiative can be taken only by the **Legislative Assembly** of that State.



2 Resolution in the State Legislative Assembly

The State Legislative Assembly must pass such a resolution by **Special Majority**.

Special Majority =

- Majority of the total membership of the House
- Not less than two-thirds of the members present and voting

3 Final Power Lies with Parliament

Parliament can create or abolish the Legislative Council in that State by making a law.

In Parliament, this law is passed only by **Simple Majority**.



Conclusion: The initiative is taken by the State Legislative Assembly, but the final decision is made by Parliament.

विधान परिषद : हाल की राज्य-स्तरीय पहलें

1 राजस्थान व असम



परिषद सृजन
के प्रस्ताव
पारित



- विधानसभाओं ने परिषद सृजन के प्रस्ताव पारित किए।
- संबंधित विधेयक 2013 से राज्यसभा में लंबित।



राज्यसभा में
लंबित

2 ओडिशा (2018) व पश्चिम बंगाल (जुलाई 2021)



परिषद सृजन
के प्रस्ताव
पारित



- विधानसभाओं ने परिषद सृजन के प्रस्ताव पारित किए।
- संसद में कार्यवाही लंबित।



कार्यवाही
लंबित

3 आंध्र प्रदेश

जनवरी 2020



विधानसभा ने परिषद उन्मूलन का प्रस्ताव पारित किया।



नवंबर 2021



यह प्रस्ताव वापस ले लिया गया।



 **परिषद कायम।**



मुख्य बिंदु :

कुछ राज्यों ने परिषद के सृजन का प्रस्ताव पारित किया है, जबकि आंध्र प्रदेश में उन्मूलन का प्रस्ताव वापस ले लिया गया।

Legislative Council: Recent State-Level Initiatives

1 Rajasthan & Assam

Resolution
for creation of
Legislative
Council



- The Legislative Assemblies passed resolutions for the creation of Legislative Councils.
- The related Bill has been pending in the Rajya Sabha since 2013.

Pending in
Rajya Sabha

2 Odisha (2018) & West Bengal (July 2021)

Resolution
for creation of
Legislative
Council



- The Legislative Assemblies passed resolutions for the creation of Legislative Councils.
- Action in Parliament is still pending.

Action
Pending

3 Andhra Pradesh

January 2020

The Assembly
passed a resolution
for the abolition of
the Legislative
Council.



November 2021

The resolution
was withdrawn.



Council Continues



Key Point

Some states passed resolutions for the creation of Legislative Councils, while Andhra Pradesh withdrew its proposal for abolition.

अनुच्छेद 170 → विधान सभाओं की संरचना (Composition of Legislative Assemblies)

- ❑ राज्य की विधान सभा
 - ✓ अधिकतम → 500 सदस्य
 - ✓ न्यूनतम → 60 सदस्य
- ❑ अपवाद :
 - ✓ सिक्किम (32)
 - ✓ मिजोरम (40)
 - ✓ गोवा (40)
- ❑ निर्वाचन की प्रकृति : प्रत्यक्ष चुनाव
 - ✓ सिक्किम विधानसभा की 32 सीटों में से **एक** **सीट संघा** के लिए आरक्षित है।
- ❑ जनसंख्या का आधार : 1971 की जनगणना
- ❑ 170(2) → आवंटित सीट का अनुपात पूरे राज्य में लगभग एक समान हो।
- ❑ अनुच्छेद 170(3) → प्रत्येक जनगणना के बाद पुनर्समायोजन
 - ✓ राज्य विधानसभा में कुल सीटों की संख्या → 1971 की जनगणना
 - ✓ निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन → 2001 की जनगणना
- ❑ संसद 'परिसीमन आयोग' (Delimitation Commission) का गठन
- ❑ अनुच्छेद 332 → अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण
- ❑ अनुच्छेद 333 → राज्यपाल द्वारा एक आंग्ल-भारतीय का मनोनयन
 - ✓ 104वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 द्वारा समाप्त

उत्तर प्रदेश (403 सीटें)	पश्चिम बंगाल (294)	महाराष्ट्र (288)
गोवा (40)	मिजोरम (40)	सिक्किम (32)
जम्मू और कश्मीर (90)	दिल्ली (70)	पुडुचेरी (30)

Article 170 → Composition of Legislative Assemblies

❑ State Legislative Assembly

- ✓ Maximum → **500 members**
- ✓ Minimum → **60 members**

❑ Exceptions:

- ✓ Sikkim (32)
- ✓ Mizoram (40)
- ✓ Goa (40)

❑ Mode of election: **Direct election**

- ✓ Of Sikkim's 32 seats, one is reserved for the **Sangha**

❑ Art. 170(2) → seats allotted in the **same population ratio**

❑ Article 170(3) → **readjustment** after each Census

✓ Total seats → **1971 Census**

✓ Delimitation of constituencies → **2001 Census**

❑ **Delimitation Commission** set up by law of Parliament

❑ Article 332 → seats reserved for **SCs and STs**

❑ Article 333 → Governor nominated one **Anglo-Indian**

✓ Discontinued by the **104th Amendment Act, 2019**

<i>Uttar Pradesh (403)</i>	<i>West Bengal (294)</i>	<i>Maharashtra (288)</i>
<i>Goa (40)</i>	<i>Mizoram (40)</i>	<i>Sikkim (32)</i>
<i>JK (90)</i>	<i>Delhi (70)</i>	<i>Puducherry (30)</i>

अनुच्छेद 171 → विधान परिषदों की संरचना (Composition of Legislative Councils)

- ❑ अधिकतम : विधान सभा की कुल सदस्य संख्या के एक-तिहाई
- ❑ न्यूनतम सीमा : 40
- ❑ कुल सदस्यों का $\frac{5}{6}$ हिस्सा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, जबकि शेष $\frac{1}{6}$ हिस्सा मनोनीत होता है:

- ❑ यह व्यवस्था अंतिम नहीं — संसद इसे बदल सकती है (अनु. 171(2));
- ❑ अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित और कुछ नामित
 - ✓ आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत (STV) द्वारा → गुप्त मतदान

अनुपात	किसके द्वारा चुने/मनोनीत जाते हैं?
1/3 सदस्य	इनका चुनाव राज्य की नगरपालिकाओं, जिला बोर्डों और अन्य स्थानीय प्राधिकारियों (जो संसद द्वारा निर्दिष्ट हों) के सदस्यों द्वारा
1/12 सदस्य	ऐसे शिक्षकों द्वारा चुने जाते हैं जो राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में कम से कम 3 वर्ष से पढ़ा रहे हों। शर्त: ये संस्थान माध्यमिक स्तर (Secondary level) से नीचे के नहीं होने चाहिए।
1/12	ऐसे व्यक्तियों द्वारा चुने जाते हैं जो कम से कम 3 वर्ष से भारत के किसी भी विश्वविद्यालय के स्नातक हों और उस राज्य में निवास कर रहे हों।
1/3 सदस्य	राज्य के विधायकों द्वारा उन व्यक्तियों में से चुने जाते हैं, जो विधान सभा के सदस्य नहीं हैं। (अर्थात् विधायक स्वयं को नहीं चुन सकते)।
1/6 सदस्य	171(5) → राज्यपाल द्वारा नामित – साहित्य, विज्ञान, कला (Art), समाज सेवा, सहकारी आंदोलन (Cooperative Movement)

Article 171 → Composition of Legislative Councils

- ❑ Maximum: **one-third** of the Assembly's total membership
- ❑ Minimum: **40** members
- ❑ **5/6** indirectly elected, **1/6** nominated:

- ❑ Parliament can change it by law (Art. 171(2))
- ❑ Partly **indirectly elected**, partly **nominated**
 - ✓ Elected by **proportional representation** (single transferable vote), by **secret ballot**

Share	Elected / nominated by
1/3	Members of municipalities, district boards and other local authorities specified by Parliament
1/12	Teachers with 3+ years' teaching in State institutions of at least secondary school level
1/12	Graduates of 3+ years' standing from any university in India, residing in the State
1/3	MLAs, from among persons who are not MLAs
1/6	Art. 171(5) → nominated by the Governor: literature, science, art, cooperative movement, social service

अनुच्छेद 172 → राज्य विधानमंडलों की अवधि

❑ अनुच्छेद 172 (1)

- ✓ सामान्य कार्यकाल : प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष
- ✓ समय से पूर्व विघटन : राज्यपाल
- ✓ राष्ट्रीय आपातकाल (352) के दौरान संसद विधि द्वारा कार्यकाल एक बार में एक वर्ष तक (कितनी भी बार) बढ़ा सकती है; परंतु आपातकाल समाप्त होने के बाद 6 माह से अधिक नहीं।

❑ अनुच्छेद 172 (2)

- ✓ विधान परिषद स्थायी सदन है।
- ✓ यथाशक्य (As nearly as possible) एक-तिहाई (1/3) सदस्य हर दूसरे वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 → विधान परिषद {धारा 156}
और राज्यसभा {धारा 154} के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष

अनुच्छेद 173 → सदस्यों की योग्यताएं

- ❑ भारत का नागरिक
- ❑ निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष शपथ — नामांकन भरते समय एक उम्मीदवार के रूप में
- ❑ आयु:
 - ✓ विधानसभा — कम से कम 25 वर्ष;
 - ✓ विधान परिषद — कम से कम 30 वर्ष
- ❑ संसद द्वारा निर्धारित अन्य अर्हताएँ।

अनुच्छेद 173 केवल 'सकारात्मक योग्यताओं' (Qualifications) की बात करता है (यानी सदस्य बनने के लिए क्या चाहिए)। जबकि सदस्य को पद से हटाने या अयोग्य ठहराने वाली 'निर्हरताएं' (Disqualifications - जैसे लाभ का पद, मानसिक अस्वस्थता, दिवालियापन आदि) अनुच्छेद 191 में दी गई हैं।

Article 172 → Term of Legislatures

❑ Article 172(1)

- ✓ Normal term: **5 years** from its first meeting
- ✓ Earlier dissolution: by the **Governor**
- ✓ In a **National Emergency (Art. 352)**, Parliament may extend the term by law **one year at a time**, but not beyond **6 months** after the Emergency ends

❑ Article 172(2)

- ✓ The Legislative Council is a **permanent House**; it cannot be dissolved
- ✓ About **one-third** of its members retire every second year

RPA, 1951 → MLCs {Sec. 156} and Rajya Sabha members {Sec. 154} serve 6-year terms

Article 173 → Qualifications

- ❑ Must be a **citizen of India**
- ❑ Must take an **oath** before a person authorised by the Election Commission when filing nomination
- ❑ **Age:**
 - ✓ Legislative Assembly: at least **25 years**
 - ✓ Legislative Council: at least **30 years**
- ❑ Other qualifications prescribed by **Parliament**

Art. 173 sets out qualifications only. Disqualifications (office of profit, unsound mind, insolvency, etc.) are in Article 191.

अनुच्छेद 174 → सत्र (Sessions), सत्रावसान (Prorogation) और विघटन (Dissolution)

□ राज्यपाल

- ✓ सत्र बुलाना (Summoning the Sessions)
- ✓ सत्रावसान (Prorogue)
- ✓ विघटन (Dissolve)

□ समय सीमा (Maximum Gap) : 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं

- ✓ विधानमंडल के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की पहली बैठक के बीच 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए।

अनुच्छेद 175 और 176 → राज्यपाल का राज्य विधानमंडल में अभिभाषण (Address)

□ अनुच्छेद 175 : राज्यपाल का 'विशेष'

अभिभाषण : ऐच्छिक अनिवार्य

- ✓ दोनों सदनों को संबोधित
- ✓ राज्यपाल सदन को संदेश भेज सकते हैं।

□ अनुच्छेद 176 : राज्यपाल का 'विशेष' अभिभाषण : अनिवार्य

- ✓ हर आम चुनाव के बाद नई विधानसभा के पहले सत्र की शुरुआत में।
- ✓ प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र (आमतौर पर बजट सत्र) की शुरुआत में।

Article 174 → Sessions, Prorogation and Dissolution

❑ Governor

- ✓ Summons the House(s)
- ✓ Prorogues the House(s)
- ✓ Dissolves the Legislative Assembly

❑ Maximum gap: 6 months

- ✓ The gap between the last sitting of one session and the first sitting of the next must not exceed 6 months.

Articles 175 and 176 → Governor's Address to the Legislature

❑ Article 175: right to address (optional)

- ✓ Addresses either House or both Houses together
- ✓ May send messages to the House(s)

❑ Article 176: special address (mandatory)

- ✓ At the first session after each general election
- ✓ At the first session of each year (usually the Budget session)

अनुच्छेद 177 → मंत्रियों और महाधिवक्ता (Advocate-General) के अधिकार

- ❑ मंत्री तथा महाधिवक्ता (Advocate General) → दोनों सदनों की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार
- ❑ वे विधानमंडल की उस समिति की कार्यवाही में भी बोल सकते हैं और भाग ले सकते हैं, जिसके वे सदस्य नामित किए गए हों।
- ❑ मंत्री अपने सदन में मतदान कर सकता है, लेकिन महाधिवक्ता को विधानमंडल में मतदान का अधिकार नहीं है।

अनुच्छेद 178 से 181 → विधान सभा के अधिकारी (अध्यक्ष और उपाध्यक्ष)

- ❑ अनुच्छेद 178 → विधानसभा अपने दो सदस्यों को सभापति और उपसभापति के रूप में चुनेगी (choose)
- ❑ अनुच्छेद 179 (हटाना व त्यागपत्र) → तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत (Effective Majority)
 - अध्यक्ष अपना इस्तीफा उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा अध्यक्ष को सौंपता है।
- ❑ अनुच्छेद 180 (कार्यकारी अध्यक्ष) → जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो या वह अनुपस्थित हो, तो अध्यक्ष के कर्तव्यों का पालन उपाध्यक्ष करेगा। यदि उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित हो, तो राज्यपाल द्वारा नियुक्त कोई अन्य सदस्य यह कार्य करेगा।
- ❑ अनुच्छेद 181 (हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन) → : वे सदन में उपस्थित रहते हुए भी पीठासीन (Preside) नहीं होंगे। वे कार्यवाही में भाग ले सकते हैं और प्रथमतः वोट भी दे सकते हैं, लेकिन 'निर्णायक मत' (Casting vote) नहीं दे सकते।

Article 177 → Rights of Ministers and the Advocate-General

- ❑ **Ministers and the Advocate-General** → may speak in and take part in both Houses
- ❑ Also in any legislative committee they are named to
- ❑ Ministers vote in their own House; the Advocate-General has **no right to vote**

Articles 178–181 → Speaker and Deputy Speaker

- ❑ Article 178 → the Assembly **elects** its Speaker and Deputy Speaker from among its members
- ❑ Article 179 (removal and resignation) → removal by **effective majority**, after **14 days' notice**
 - The Speaker resigns to the Deputy Speaker, and the Deputy Speaker to the Speaker
- ❑ Article 180 (acting Speaker) → if the post is vacant, the Deputy Speaker acts; if both are vacant, a member appointed by the **Governor**
- ❑ Article 181 (removal resolution pending) → the Speaker **cannot preside**, but may speak and vote in the **first instance**; **no casting vote**

अनुच्छेद 182 से 185 → विधान परिषद के अधिकारी (सभापति और उपसभापति)

- ❑ अनुच्छेद 182 → विधान परिषद अपने दो सदस्यों को सभापति और उपसभापति के रूप में चुनेगी (choose)
 - ✓ परिषद की कार्यवाही में भाग लेने, बोलने और प्रथमतः (First instance) वोट का अधिकार होता है।
- ❑ अनुच्छेद 183 → रिक्त होना, त्यागपत्र देना, या हटाया जाना।
 - ✓ सभापति → त्यागपत्र → उपसभापति
 - ✓ उपसभापति → त्यागपत्र → सभापति
 - ✓ पद से हटाना → 14 दिन की पूर्व सूचना के बाद तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत (Effective Majority) से
- ❑ अनुच्छेद 184 → जब सभापति का पद रिक्त हो, तो कर्तव्यों का पालन उपसभापति करेगा। यदि उपसभापति भी अनुपस्थित हो, तो राज्यपाल द्वारा नियुक्त कोई अन्य सदस्य यह कार्य करेगा।
- ❑ अनुच्छेद 185 → जब सभापति या उपसभापति को उनके पद से हटाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन हो, तो अध्यक्षता नहीं करेंगे।
- ❑ अनुच्छेद 186 → पीठासीन अधिकारियों के वेतन और भत्तों
 - ✓ राज्य विधानमंडल द्वारा कानून (विधि) बनाकर
 - ✓ राज्य की संचित निधि (Consolidated Fund of the State) पर भारित (Charged) व्यय
- ❑ अनुच्छेद 187 → राज्य विधानमंडल के सचिवालय
 - ✓ प्रत्येक सदन) का अपना एक अलग सचिवालय
 - ✓ दोनों सदनों के लिए कुछ 'संयुक्त पदों' का सृजन
 - ✓ भर्ती और सेवा शर्तें : राज्य विधानमंडल
 - ✓ तब तक राज्यपाल → 'अध्यक्ष' और विधान परिषद के मामले में 'सभापति' के परामर्श से भर्ती और सेवा शर्तें नियम

Articles 182–185 → Council Chairman and Deputy

- ❑ Art. 182 → Council **chooses** a **Chairman** and a **Deputy**

Chairman

- ❑ Art. 183 → vacation, resignation and removal
 - ✓ Chairman resigns to the Deputy Chairman
 - ✓ Deputy Chairman resigns to the Chairman
 - ✓ Removal: **effective majority**, after **14 days'** notice
- ❑ Art. 184 → if the post is vacant, the Deputy Chairman acts; if both are vacant, a member appointed by the **Governor**
- ❑ Art. 185 → **Cannot preside** while a resolution for their removal is pending
 - ✓ They may speak and vote in the **first instance**

- ❑ **Art. 186 → Salaries of presiding officers**

- ✓ Fixed by law of the State Legislature
- ✓ **Charged** on the State's Consolidated Fund

- ❑ **Art. 187 → Secretariat of the Legislature**

- ✓ Each House has its own secretariat
- ✓ Posts common to both Houses may be created
- ✓ Recruitment and service: regulated by the **State Legislature**
- ✓ Until then: rules by the **Governor**, after consulting the Speaker/Chairman

अनुच्छेद 188 → राज्य विधानमंडल के सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान

- ❑ राज्य की विधानसभा (Legislative Assembly) और विधान परिषद (Legislative Council) के नवनिर्वाचित सदस्यों की शपथ
- ❑ **राज्यपाल या उसके द्वारा इस कार्य के लिए नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष** → प्रोटेम स्पीकर (Pro-tem Speaker)
- ❑ यह शपथ संविधान की तीसरी अनुसूची (Third Schedule) में दिए गए प्रारूप के अनुसार ली जाती है।

अनुच्छेद 189 → राज्य विधानमंडल में मतदान, रिक्तियां और गणपूर्ति (Quorum)

- ❑ 189(1) → सदन की बैठक में सभी प्रश्नों का निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत (Majority) से किया जाएगा।
 - ✓ अध्यक्ष/सभापति की भूमिका → मात्र निर्णायक मत (Casting Vote)
- ❑ 189(2) → यदि राज्य विधानमंडल के किसी सदन में कोई स्थान रिक्त है, तो भी सदन को कार्य करने की शक्ति होगी।
- ❑ 189(3) → दस सदस्य या सदन की कुल सदस्य संख्या का दसवां हिस्सा (1/10th),
- ❑ 189(4) → यदि गणपूर्ति (Quorum) नहीं है, तो यह अध्यक्ष या सभापति का कर्तव्य है कि वह सदन को स्थगित (Adjourn) कर दे या कोरम पूरा होने तक बैठक को निलंबित कर दे।

Article 188 → Oath or affirmation by members of the State Legislature

- ❑ Oath of newly elected members of the State Legislative Assembly and Legislative Council
- ❑ **Before the Governor or a person appointed by him for this purpose** → Pro-tem Speaker
- ❑ This oath is taken in the form given in the Third Schedule of the Constitution

Article 189 → Voting, vacancies and quorum in the State Legislature

- ❑ 189(1) → All questions at a House sitting shall be decided by a majority of the members present and voting
 - ✓ Role of the Speaker/Chairman → only a Casting Vote
- ❑ 189(2) → Even if any seat in a House of the State Legislature is vacant, the House shall have the power to act
- ❑ 189(3) → **Ten members or one-tenth (1/10th) of the total membership of the House**
- ❑ 189(4) → If there is no quorum, it is the duty of the Speaker or Chairman to adjourn the House or suspend the sitting until the quorum is met

अनुच्छेद 190 → स्थानों का रिक्त होना (Vacation of Seats)

- ❑ कोई भी व्यक्ति एक ही समय में राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों (विधानसभा और विधान परिषद) का सदस्य नहीं हो सकता।
- ❑ कोई सदस्य **अध्यक्ष (Speaker) या सभापति (Chairman) को हस्तलिखित त्यागपत्र** सौंप सकता है।
 - ✓ 33वें संविधान संशोधन (1974) : अध्यक्ष या सभापति सदस्य का त्यागपत्र तभी स्वीकार करेगा जब वह संतुष्ट हो कि त्यागपत्र "स्वैच्छिक और असली" (Voluntary and Genuine) है।
 - ✓ यदि कोई सदस्य अनुच्छेद 191(1) या अनुच्छेद 191(2) के तहत अयोग्य घोषित हो जाता है।
- ❑ **60 दिनों की अनुपस्थिति (Absence for 60 Days):**
 - ✓ यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना सभी बैठकों से लगातार 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है, तो सदन (House) उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकता है (ध्यान दें: यह स्वतः रिक्त नहीं होता, सदन को घोषणा करनी पड़ती है)।
 - ✓ इन 60 दिनों की गणना करते समय उस अवधि को नहीं गिना जाएगा जिसके दौरान सदन का सत्रावसान (Prorogued) हो गया हो, या सदन लगातार 4 दिनों से अधिक के लिए स्थगित (Adjourned) रहा हो।

Article 190 → Vacation of seats

- ❑ No person can be a member of both Houses of the State Legislature (Legislative Assembly and Legislative Council) at the same time
- ❑ A member may submit a handwritten resignation to the Speaker or Chairman
 - ✓ 33rd Constitutional Amendment (1974): The Speaker or Chairman shall accept a member's resignation only when satisfied that it is "voluntary and genuine"
 - ✓ If a member is declared disqualified under Article 191(1) or Article 191(2)
- ❑ **Absence for 60 Days :**
 - ✓ If a member remains absent from all sittings for 60 consecutive days without the House's permission, the House can declare his seat vacant (Note: the seat does not fall vacant automatically; the House must declare it)
 - ✓ While counting these 60 days, the period during which the House is prorogued, or adjourned for more than 4 consecutive days, shall not be counted.

अनुच्छेद 191 → राज्य विधानमंडल के सदस्यों की सदस्यता के लिए अयोग्यताएं

- ❑ भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है।
 - ✓ राज्य विधानमंडल कानून बनाकर यह घोषित कर सकता है कि कोई विशेष पद धारण करने वाले को अयोग्य नहीं माना जाएगा।
 - ✓ केवल संघ (Union) या राज्य का मंत्री (Minister) होने मात्र से किसी व्यक्ति को लाभ के पद पर नहीं माना जाएगा।
- ❑ विकृत चित्त (Unsound Mind) : सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसी स्पष्ट घोषणा
- ❑ न्यायालय द्वारा दिवालिया (Undischarged Insolvent)
- ❑ वह भारत का नागरिक नहीं है
- ❑ यदि वह संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के तहत अयोग्य घोषित कर दिया जाता है।
- ❑ अनुच्छेद 191(2) : दल-बदल (Anti-Defection) के आधार पर अयोग्यता
 - ✓ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (RPA, 1951)

आधार	अनु. 191(1) व RPA की निरर्हता	दल-बदल (दसवीं अनुसूची)
निर्णयकर्ता	राज्यपाल	विधानसभा अध्यक्ष / परिषद सभापति
परामर्श	निर्वाचन आयोग की राय – बाध्यकारी	कोई बाध्यकारी परामर्श नहीं
न्यायिक समीक्षा	हाँ	हाँ – किहोतो होलोहन बनाम जाचिल्हू (1992)

Article 191 → Disqualifications for membership of the State Legislature

- ❑ Holds any office of profit under the Government of India or any State Government
 - ✓ The State Legislature may, by law, declare that the holder of a particular office shall not be disqualified
 - ✓ Merely being a Minister of the Union or of a State does not mean a person holds an office of profit
- ❑ Unsound Mind : a clear declaration to that effect by a competent court.
- ❑ Declared an insolvent by a court (Undischarged Insolvent)
- ❑ He is not a citizen of India
- ❑ If he is disqualified under any law made by Parliament
- ❑ **Article 191(2): Disqualification on the ground of defection (Anti-Defection)**
 - ✓ Representation of the People Act, 1951 (RPA, 1951)

Basis	Disqualification under Art. 191(1) & RPA	Defection (Tenth Schedule)
Deciding Authority	Governor	Speaker of the Assembly / Chairman of the Council
Consultation	Election Commission's opinion: binding	No binding consultation
Judicial Review	Yes	Yes: Kihoto Hollohan vs Zachillhu (1992)

अनुच्छेद 193	○ बिना शपथ लिए या अयोग्य होते हुए बैठने और मतदान करने पर जुर्माना (Penalty) ○ 500 रुपये प्रतिदिन का जुर्माना → राज्य के लिए देय ऋण (Debt due to the State) के रूप में
अनुच्छेद 194	○ विधानमंडलों और उनके सदस्यों के विशेषाधिकार (Privileges and Immunities) ○ सदन या समिति → सदस्य द्वारा कही गई बात मत (Vote) के लिए न्यायालय (Court) में उत्तरदायी नहीं ○ किसी रिपोर्ट, पेपर या कार्यवाही के प्रकाशन पर भी न्यायिक उन्मुक्ति प्राप्त है।
अनुच्छेद 195	○ सदस्यों के वेतन और भत्ते (Salaries and Allowances) ○ निर्धारण → राज्य विधानमंडल द्वारा ○ विधायकों के वेतन → राज्य की संचित निधि पर भारित (Charged) नहीं ○ विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा विधान परिषद के सभापति और उपसभापति का → भारित

Article 193	○ Penalty for sitting and voting without taking the oath or while disqualified ○ A penalty of ₹500 per day → recoverable as a debt due to the State
Article 194	○ Privileges and immunities of the Legislatures and their members ○ House or Committee → a member is not answerable in any Court for anything said or any vote given ○ Judicial immunity is also available for the publication of any report, paper or proceedings
Article 195	○ Salaries and Allowances ○ Determination → by the State Legislature ○ Salaries of legislators → not charged on the Consolidated Fund of the State ○ Of the Speaker and Deputy Speaker of the Legislative Assembly and the Chairman and Deputy Chairman of the Legislative Council → Charged

5) राज्य विधानमंडल की विधायी प्रक्रिया (Legislative)

अनुच्छेद 196 → विधेयकों के पुरःस्थापन (Introduction)

- ❑ धन विधेयक और विशिष्ट वित्त विधेयकों को छोड़कर, कोई भी साधारण विधेयक राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है।
- ❑ गतिरोध निवारण हेतु संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है
 - ✓ जब कोई विधेयक विधान परिषद में प्रस्तुत किया जाता है, और यदि विधान सभा असहमत होती है, तो विधेयक समाप्त हो जाता है, और भाग VI में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है।
- ❑ विधेयक को कानून बनने के लिए दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाना चाहिए और राज्यपाल द्वारा स्वीकृत किया जाना चाहिए।

5) Legislative Process of the State Legislature

Article 196 → Introduction of Bills

- ❑ Except Money Bills and certain Financial Bills, any Ordinary Bill may be introduced in either House of the State Legislature
- ❑ There is no provision for a joint sitting to resolve a deadlock
 - ✓ When a Bill is introduced in the Legislative Council and the Legislative Assembly disagrees, the Bill lapses, and Part VI has no provision for a joint sitting.
- ❑ For a Bill to become law, it must be passed by both Houses and assented to by the Governor

अनुच्छेद 197 → साधारण विधेयकों के संबंध में विधान परिषद की शक्तियों पर प्रतिबंध

- ❑ जब विधानसभा किसी सामान्य विधेयक को पारित करके विधान परिषद को भेजती है, तो निम्नलिखित तीन स्थितियों में विधानसभा विधेयक को दोबारा पारित कर सकती है :-
 - ✓ विधान परिषद विधेयक को अस्वीकार कर दे।
 - ✓ विधान परिषद के समक्ष विधेयक रखे जाने के बाद **तीन महीने से अधिक समय** बीत जाए, लेकिन परिषद उसे पारित न करे।
 - ✓ विधान परिषद विधेयक में ऐसे संशोधन करके पारित करे, जिनसे विधानसभा सहमत न हो।
- ❑ जब विधानसभा विधेयक को दूसरी बार पारित करके विधान परिषद को भेजती है, तब निम्नलिखित में से कोई स्थिति उत्पन्न होने पर विधेयक दोनों सदनों से पारित माना जाएगा:
 - ✓ विधान परिषद विधेयक को अस्वीकार कर दे।
 - ✓ परिषद के समक्ष विधेयक रखे जाने के बाद **एक महीने से अधिक समय** बीत जाए, लेकिन वह इसे पारित न करे।
 - ✓ परिषद ऐसे संशोधनों के साथ विधेयक पारित करे, जिन्हें विधानसभा स्वीकार न करे।
- ❑ राज्यसभा एक शक्तिशाली 'संशोधक सदन' (Revising Chamber) है, जबकि विधान परिषद मात्र एक 'विलंबकारी सदन' (Delaying Chamber) है।

Article 197 → Restrictions on the powers of the Legislative Council with respect to Ordinary Bills

- ❑ When the Legislative Assembly passes an Ordinary Bill and sends it to the Legislative Council, the Assembly may pass the Bill again in the following three situations :-
 - ✓ The Legislative Council rejects the Bill.
 - ✓ More than three months pass after the Bill is laid before the Legislative Council, but the Council does not pass it
 - ✓ The Legislative Council passes the Bill with amendments to which the Legislative Assembly does not agree.
- ❑ When the Legislative Assembly passes the Bill a second time and sends it to the Legislative Council, the Bill shall be deemed passed by both Houses if any of the following situations arises :
 - ✓ The Legislative Council rejects the Bill
 - ✓ More than one month passes after the Bill is laid before the Council, but it does not pass it.
 - ✓ The Council passes the Bill with amendments which the Legislative Assembly does not accept
- ❑ **The Rajya Sabha is a powerful 'Revising Chamber', whereas the Legislative Council is merely a 'Delaying Chamber'.**

अनुच्छेद 198 → धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया

- ❑ धन विधेयक विधान परिषद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।
- ❑ विधान परिषद को सिफारिशों के लिए → 14 दिनों के

अनुच्छेद 199 → धन विधेयकों की परिभाषा

- ❑ किसी कर को लगाना, समाप्त करना या परिवर्तन।
- ❑ राज्य द्वारा ऋण लेने या गारंटी देने का विनियमन तथा राज्य की वित्तीय बाध्यताओं से संबंधित कानून में संशोधन।
- ❑ राज्य की संचित निधि या आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा।
- ❑ राज्य की संचित निधि से धन का विनियोग (Appropriation)।
- ❑ किसी व्यय को राज्य की संचित निधि पर भारित घोषित करना।
- ❑ राज्य की संचित निधि या लोक लेखे में धन की प्राप्ति तथा ऐसे धन की अभिरक्षा या निर्गमन।

❑ अनुच्छेद 199(2) : धन विधेयक नहीं

- ✓ जुर्माना या अन्य आर्थिक दंड लगाना।
- ✓ लाइसेंस के लिए शुल्क लेना।
- ✓ प्रदान की गई सेवाओं के लिए शुल्क लेना।
- ✓ स्थानीय प्राधिकरण या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनों के लिए कर लगाना, समाप्त करना, माफ करना, बदलना या उसका विनियमन करना।

❑ अनुच्छेद 199(3) : विधानसभा अध्यक्ष का अंतिम निर्णय

Article 198 → Special procedure with respect to Money Bills

- ❑ A Money Bill cannot be introduced in the Legislative Council.
- ❑ For the Legislative Council's recommendations → 14 days

Article 199 → Definition of Money Bills

- ❑ Imposition, abolition or alteration of any tax.
 - ❑ Regulation of borrowing or giving of guarantees by the State, and amendment of the law relating to the financial obligations of the State.
 - ❑ Custody of the Consolidated Fund or Contingency Fund of the State.
 - ❑ Appropriation of money out of the Consolidated Fund of the State.
 - ❑ Declaring any expenditure to be charged on the Consolidated Fund of the State
 - ❑ Receipt of money into the Consolidated Fund or the Public Account of the State, and the custody or issue of such money
- ❑ **Article 199(2): Not a Money Bill**
 - ✓ Imposition of fines or other pecuniary penalties.
 - ✓ Demand of fees for licences
 - ✓ Demand of fees for services rendered.
 - ✓ Imposition, abolition, remission, alteration or regulation of any tax by a local authority or body for local purposes
 - ❑ **Article 199(3) : Final decision of the Speaker of the Legislative Assembly**

अनुच्छेद 200 → विधेयकों पर राज्यपाल की अनुमति (Assent to Bills)

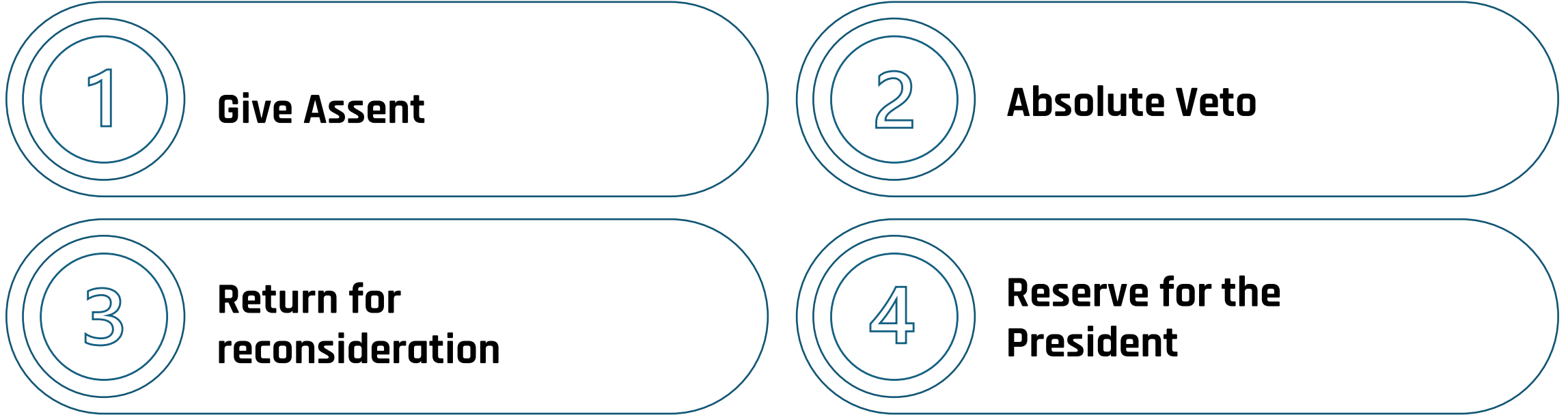
❑ जब कोई विधेयक राज्यपाल के पास आता है, तो उसके पास चार विकल्प होते हैं:

- | | |
|--|---|
|  1 अनुमति देना (Give Assent) |  2 अनुमति रोकना (Absolute Veto) |
|  3 पुनर्विचार के लिए लौटाना |  4 राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखना |

- ❑ वह पूरे विधेयक या उसके किसी विशेष प्रावधान पर पुनर्विचार का अनुरोध कर सकता है।
- ❑ विधानमंडल विधेयक को संशोधन सहित या बिना संशोधन के दोबारा पारित कर सकता है।
- ❑ विधेयक दोबारा पारित होकर राज्यपाल के समक्ष आने पर राज्यपाल उसकी अनुमति दोबारा नहीं रोक सकता।
- ❑ **अनिवार्य आरक्षण :** यदि कोई विधेयक ऐसा है जो राज्य के उच्च न्यायालय (High Court) की स्थिति या शक्तियों को खतरे में डालता है, तो राज्यपाल के लिए उस विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना अनिवार्य है।

Article 200 → Governor's assent to Bills

❑ When a Bill comes to the Governor, he has four options :



- ❑ He may request reconsideration of the whole Bill or of any specific provision of it
- ❑ The Legislature may pass the Bill again, with or without amendments
- ❑ When the Bill, passed again, comes before the Governor, he cannot withhold his assent a second time
- ❑ **Compulsory reservation** : If a Bill endangers the position or powers of the State High Court, the Governor must reserve that Bill for the President.

अनुच्छेद 201 → राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित विधेयक

□ अनुच्छेद 200 के तहत जब राज्यपाल किसी राज्य विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित (Reserve) कर लेता है, तो उस विधेयक पर आगे की प्रक्रिया अनुच्छेद 201 के तहत तय होती है।

□ राष्ट्रपति के तीन विकल्प

- अनुमति देना (Assent)
- अनुमति रोकना (Withhold Assent)
- पुनर्विचार के लिए लौटाना (Return for Reconsideration)

✓ यदि वह धन विधेयक नहीं है, तो राष्ट्रपति राज्यपाल को निर्देश दे सकता है कि वह विधेयक को राज्य विधानमंडल के पास संदेश के साथ वापस लौटा दे।

✓ जब राष्ट्रपति के निर्देश पर विधेयक राज्य विधानमंडल को वापस मिलता है, तो विधानमंडल के लिए यह अनिवार्य है कि वह उस पर 6 महीने के भीतर पुनर्विचार करे।

अनुच्छेद 201 में कहीं भी यह नहीं लिखा है कि राष्ट्रपति दूसरी बार में अनुमति देने के लिए बाध्य है। इसका अर्थ यह है कि राज्य के विधेयकों पर राष्ट्रपति को 'पूर्ण वीटो' (Absolute Veto) प्राप्त है, जबकि संसद के विधेयकों (अनुच्छेद 111) पर उसे केवल 'निलंबनकारी वीटो' (Suspensive Veto) प्राप्त है।

Article 201 → Bills reserved for the consideration of the President

- ❑ When the Governor reserves a State Bill for the President's consideration under Article 200, the further procedure on that Bill is determined under Article 201.
- ❑ **Three options of the President**
 - **Assent**
 - **Withhold Assent**
 - **Return for Reconsideration**
 - ✓ If it is not a Money Bill, the President may direct the Governor to return the Bill to the State Legislature with a message

- ✓ When a Bill is returned to the State Legislature on the President's direction, the Legislature must reconsider it within 6 months.

Nowhere in Article 201 is it written that the President is bound to give assent the second time. This means the President has an 'Absolute Veto' over State Bills, whereas over Parliament's Bills (Article 111) he has only a 'Suspensive Veto'.

6) वित्तीय और अन्य प्रावधान (Financial and other provisions)

अनुच्छेद 202

- वार्षिक वित्तीय विवरण (राज्य का बजट)
- अनुच्छेद 202(3) : राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय
 - ✓ राज्यपाल के वेतन-समान परिलब्धियाँ, भत्ते और उसके कार्यालय से संबंधित अन्य व्यय।
 - ✓ विधानसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष तथा विधान परिषद् के सभापति एवं उपसभापति के वेतन और भत्ते।
 - ✓ राज्य के ऋण संबंधी भार, जिनमें ब्याज, ऋण चुकाने के लिए निधि संबंधी प्रभार तथा ऋण जुटाने और चुकाने से जुड़े व्यय शामिल हैं।
 - ✓ किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों से संबंधित व्यय।
 - ✓ किसी न्यायालय या मध्यस्थता अधिकरण के निर्णय, डिक्री या अधिनिर्णय की पूर्ति के लिए आवश्यक धनराशि।
 - ✓ संविधान या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून के अंतर्गत भारित घोषित अन्य व्यय।

6) Financial and other provisions

Article 202

- Annual Financial Statement (State Budget)
- Article 202(3) : Expenditure charged on the Consolidated Fund of the State
 - ✓ The Governor's salary-like emoluments, allowances and other expenditure relating to his office
 - ✓ Salaries and allowances of the Speaker and Deputy Speaker of the Legislative Assembly and the Chairman and Deputy Chairman of the Legislative Council.
 - ✓ Debt charges of the State, including interest, sinking fund charges, and expenditure connected with raising and repaying loans.
 - ✓ Expenditure relating to the salaries and allowances of the Judges of any High Court
 - ✓ Sums required to satisfy any judgment, decree or award of any court or arbitral tribunal
 - ✓ Any other expenditure declared to be so charged under the Constitution or a law made by the State Legislature

अनुच्छेद 203	○ विधानमंडल में प्राकलनों (Estimates) के संबंध में प्रक्रिया ○ यह अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि बजट में दिखाए गए खर्चों पर विधानमंडल में कैसे चर्चा और मतदान होगा। ○ किसी भी अनुदान की मांग को राज्यपाल की सिफारिश के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है।
अनुच्छेद 204	○ विनियोग विधेयक (Appropriation Bills) ○ राज्य की संचित निधि से कोई भी धन केवल और केवल विनियोग विधेयक (Appropriation Bills) के तहत ही निकाला जा सकता है, अन्यथा नहीं।
अनुच्छेद 205	○ अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान (Supplementary, Additional or Excess Grants)
अनुच्छेद 206	○ लेखानुदान, प्रत्ययानुदान और अपवादानुदान (Votes on Account, Votes of Credit and Exceptional Grants)
अनुच्छेद 207	○ वित्त विधेयकों के संबंध में विशेष उपबंध (Special provisions as to financial Bills)

Article 203	○ Procedure in the Legislature with respect to Estimates ○ This Article clarifies how the expenditure shown in the budget will be discussed and voted upon in the Legislature ○ No demand for a grant can be made without the recommendation of the Governor.
Article 204	○ Appropriation Bills ○ No money can be withdrawn from the Consolidated Fund of the State except under an Appropriation Bill, and in no other way.
Article 205	○ Supplementary, Additional or Excess Grants) (Supplementary, Additional or Excess Grants
Article 206	○ Votes on Account, Votes of Credit and Exceptional Grants
Article 207	○ Special provisions as to financial Bills) (Special provisions as to Financial Bills

अनुच्छेद 208	○ प्रक्रिया के नियम (Rules of Procedure) ○ राज्य विधानमंडल का प्रत्येक सदन (विधानसभा और विधान परिषद) संविधान के प्रावधानों के अधीन रहते हुए अपनी प्रक्रिया और कार्य-संचालन के लिए स्वतंत्र रूप से नियम बना सकता है। ○ एक सदन से दूसरे सदन के बीच संचार की प्रक्रिया के नियम राज्यपाल बनाएगा। ऐसा करने से पहले वह विधानसभा अध्यक्ष (Speaker) और विधान परिषद के सभापति (Chairman) से परामर्श करेगा। ○ यह नियम बनाने की शक्ति असीमित नहीं है।
अनुच्छेद 209	○ राज्य विधानमंडल, वित्तीय कार्यों (जैसे विनियोग विधेयक, अनुदान की मांगें आदि) को समय के भीतर पूरा करने के लिए, कानून बनाकर अपनी प्रक्रिया को विनियमित कर सकता है।
अनुच्छेद 210	○ विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा (Language to be used in the Legislature) ○ राजभाषा (Official Language) या राजभाषाओं में, या हिंदी में, या अंग्रेजी ○ सदन का पीठासीन अधिकारी → मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दी

Article 208

- Rules of Procedure
- Each House of the State Legislature (Legislative Assembly and Legislative Council), subject to the provisions of the Constitution, may independently make rules for its procedure and conduct of business
- The Governor shall make rules for the procedure of communication between the two Houses. Before doing so, he shall consult the Speaker of the Legislative Assembly and the Chairman of the Legislative Council
- This rule-making power is not unlimited.

Article 209

- The State Legislature may, by law, regulate its procedure so as to complete financial business (such as Appropriation Bills, demands for grants, etc.) within time.

Article 210

- Language to be used in the Legislature) (Language to be used in the Legislature
- In the Official Language or Official Languages, or in Hindi, or in English
- Presiding Officer of the House → may permit a member to address the House in his mother tongue

अनुच्छेद 211

- विधानमंडल में चर्चा पर निर्बंधन (Restriction on discussion in the Legislature)
- राज्य विधानमंडल में सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) या किसी उच्च न्यायालय (High Court) के किसी न्यायाधीश द्वारा **अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए आचरण** (Conduct in discharge of duties) के विषय में कोई चर्चा नहीं की जाएगी।
- राज्य विधानमंडल में यह प्रतिबंध **पूर्णतः असीमित (Absolute)** है।

अनुच्छेद 212

- न्यायालयों द्वारा विधानमंडल की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना
- राज्य विधानमंडल की किसी कार्यवाही की वैधता को केवल प्रक्रिया में कथित अनियमितता (Irregularity of Procedure) के आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।
- विधानमंडल का कोई भी अधिकारी या सदस्य (जैसे विधानसभा अध्यक्ष या सभापति), जिसमें प्रक्रिया को विनियमित करने या कार्य-संचालन की शक्तियां निहित हैं, अपने इन अधिकारों के प्रयोग के लिए किसी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र (Jurisdiction) के अधीन नहीं होगा।

Article 211

- Restriction on discussion in the Legislature
- No discussion shall take place in the State Legislature with respect to the conduct of any Judge of the Supreme Court or of a High Court in the discharge of his duties.
- This restriction in the State Legislature is completely unlimited (Absolute)

Article 212

- Courts not to inquire into proceedings of the Legislature
- The validity of any proceeding of the State Legislature cannot be challenged in court merely on the ground of an alleged irregularity of procedure.
- No officer or member of the Legislature (such as the Speaker or Chairman) in whom powers are vested to regulate procedure or conduct business shall be subject to the jurisdiction of any court for the exercise of those powers

अध्याय 22 : राज्यपाल की शक्तियाँ (Powers)



Chapter 22 : Powers of the Governor



1) कार्यकारी शक्तियाँ

- ❑ **154** — राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में
- ❑ **162** — राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों तक विस्तृत है।
- ❑ **163** — राज्यपाल सामान्यतः मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद् की सहायता और सलाह पर कार्य करता है
 - ✓ अपवाद : संवैधानिक विवेकाधिकार
- ❑ **164** — मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मंत्री
 - ✓ राज्यपाल के प्रसादपर्यंत
 - ✓ छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और ओडिशा में जनजातीय कल्याण मंत्री का होना अनिवार्य है।
- ❑ **165** — महाधिवक्ता की नियुक्ति
- ❑ **166** — सभी सरकारी कार्य राज्यपाल के नाम से होते हैं।
- ❑ **167** — मुख्यमंत्री से प्रशासनिक मामलों और विधायी प्रस्तावों की जानकारी माँग सकता है।
- ❑ **243K** — राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति
- ❑ **316-317** — राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है,
- ❑ **356** — संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राज्यपाल राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेज सकता है। राष्ट्रपति शासन में वह राष्ट्रपति के अधीन राज्य का प्रशासन संचालित करता है।
- ❑ **विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति** : कुलपतियों की नियुक्ति कर सकता है। यह संवैधानिक नहीं, वैधानिक शक्ति है

1) Executive Powers

- ❑ **154** — The executive power of the State is vested in the Governor
- ❑ **162** — The executive power of the State extends to matters in the State List and the Concurrent List
- ❑ **163** — The Governor generally acts on the aid and advice of the Council of Ministers headed by the Chief Minister
 - ✓ Exception : Constitutional discretion
- ❑ **164** — Appoints the Chief Minister and other Ministers. Ministers hold office during the pleasure of the Governor
 - ✓ In Chhattisgarh, Jharkhand, Madhya Pradesh and Odisha, having a Minister in charge of tribal welfare is mandatory
- ❑ **165** — Appointment of the Advocate General
- ❑ **166** — All government actions are taken in the name of the Governor
- ❑ **167** — May seek information from the Chief Minister on administrative matters and legislative proposals
- ❑ **243K** — Appointment of the State Election Commissioner
- ❑ **316–317** — The Governor appoints the Chairman and members of the State Public Service Commission
- ❑ **356** — On failure of the constitutional machinery, the Governor may send a report to the President. Under President's Rule, he runs the State administration under the President.
- ❑ **Chancellor of Universities** : May appoint Vice-Chancellors. This is a statutory power, not a constitutional one

2) विधायी शक्तियाँ

- ❑ **168** — राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग है।
- ❑ **174** — आहूत करना (Summon), सत्रावसान करना (Prorogue) तथा विधानसभा को विघटित करना।
- ❑ **175** — सदन को संबोधित कर सकता है तथा लंबित विधेयक या अन्य विषय पर संदेश भेज सकता है।
- ❑ **176** — प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र तथा प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र के आरंभ में विशेष अभिभाषण देता है।
- ❑ **171** — विधान परिषद के लगभग 1/6 सदस्यों को नामित करता है। क्षेत्र—साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा।

- ❑ **192** — अनु. 191(1) के अंतर्गत निरर्हता का निर्णय निर्वाचन आयोग की बाध्यकारी राय के अनुसार करता है।
- ❑ **200** — विधेयक को अनुमति देना, अनुमति रोकना, गैर-धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटाना या राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करना।
- ❑ **213** — अध्यादेश
- ❑ राज्यपाल द्वारा विधानमंडल के समक्ष प्रतिवेदन (Reports) रखवाना
 - ✓ राज्य वित्त आयोग का प्रतिवेदन (243-I और 243-Y)
 - ✓ राज्य लोक सेवा आयोग का प्रतिवेदन (323)
 - ✓ CAG राज्य के खातों (Accounts of a State) से संबंधित अपनी ऑडिट रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को नहीं, बल्कि सीधे संबंधित राज्य के राज्यपाल को सौंपता है।

2) Legislative Powers

- ❑ **168** — The Governor is an integral part of the State Legislature.
- ❑ **174** — Summoning, proroguing, and dissolving the Legislative Assembly
- ❑ **175** — May address the House and send messages regarding a pending Bill or any other matter
- ❑ **176** — Delivers a special address at the commencement of the first session after each general election and of the first session of each year.
- ❑ **171** — Nominates about 1/6th of the members of the Legislative Council. Fields — literature, science, art, the cooperative movement and social service.
- ❑ **192** — Decides disqualification under Art. 191(1) in accordance with the binding opinion of the Election Commission
- ❑ **200** — Giving assent to a Bill, withholding assent, returning a non-Money Bill for reconsideration, or reserving it for the President's consideration
- ❑ **213** — Ordinance
- ❑ Governor causing Reports to be laid before the Legislature
 - ✓ Report of the State Finance Commission (243-I and 243-Y)
 - ✓ Report of the State Public Service Commission (323)
 - ✓ The CAG submits his audit report relating to the Accounts of a State not to the President of India, but directly to the Governor of the State concerned

3) वित्तीय शक्तियाँ

- ❑ **202** — वार्षिक वित्तीय विवरण राज्य विधानमंडल के समक्ष
- ❑ **203(3)** — राज्यपाल की सिफारिश के बिना किसी अनुदान की माँग नहीं की जा सकती।
- ❑ **207** — धन विधेयक, राज्यपाल की सिफारिश के बिना न तो प्रस्तुत (Introduce) किया जाएगा और न ही प्रस्तावित (Moved) किया जाएगा।
- ❑ **207(3)** — राज्य की संचित निधि से व्यय करने वाला विधेयक राज्यपाल की सिफारिश के बिना संबंधित सदन द्वारा पारित नहीं किया जा सकता।
- ❑ **243-I** — प्रत्येक पाँच वर्ष में राज्य वित्त आयोग का गठन

- ❑ **267(2)** — राज्य की आकस्मिकता निधि, राज्यपाल के अधिकार में रहती है।

4) न्यायिक शक्तियाँ

- ❑ **161** — क्षमादान शक्ति :
- ❑ **217** — राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय संबंधित राज्यपाल से परामर्श करता है।
- ❑ **219** — उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ
- ❑ **233** — उच्च न्यायालय के परामर्श से जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदस्थापना तथा पदोन्नति करता है।
- ❑ **234** — जिला न्यायाधीशों के अतिरिक्त राज्य की न्यायिक सेवा में नियुक्तियाँ

3) Financial Powers

- ❑ **202** — Annual Financial Statement before the State Legislature.
- ❑ **203(3)** — No demand for a grant can be made without the Governor's recommendation
- ❑ **207** — A Money Bill shall neither be introduced nor moved without the recommendation of the Governor
- ❑ **207(3)** — A Bill involving expenditure from the Consolidated Fund of the State cannot be passed by the House concerned without the Governor's recommendation
- ❑ **243-I** — Constitution of the State Finance Commission every five years.

- ❑ **267(2)** — The Contingency Fund of the State is held at the disposal of the Governor

4) Judicial Powers

- ❑ **161** — Power of pardon :
- ❑ **217** — The President consults the Governor concerned when appointing Judges of the High Court
- ❑ **219** — Oath to a Judge of the High Court.
- ❑ **233** — In consultation with the High Court, makes appointment, posting and promotion of District Judges
- ❑ **234** — Appointments to the judicial service of the State other than District Judges

पहलू	राष्ट्रपति (संसदीय विधेयक)	राज्यपाल (राज्य विधेयक)
साधारण विधेयक — विकल्प	3: अनुमति / रोकना / पुनर्विचार हेतु लौटाना	4: अनुमति / रोकना / लौटाना / राष्ट्रपति हेतु आरक्षित
पुनः पारित होने पर	अनुमति देना बाध्यकारी (निलंबनकारी वीटो)	अनुमति देना बाध्यकारी (निलंबनकारी वीटो)
धन विधेयक — विकल्प	2: अनुमति / रोकना (लौटा नहीं सकता)	3: अनुमति / रोकना / राष्ट्रपति हेतु आरक्षित (लौटा नहीं सकता)
धन विधेयक — व्यवहार	सामान्यतः अनुमति,	सामान्यतः
आरक्षित विधेयक (राष्ट्रपति — के पास)		गैर-धन: अनुमति/रोकना/लौटाने का निर्देश (6 माह); धन: अनुमति/रोकना
पॉकेट (जेबी) वीटो	हाँ (संविधान में समय-सीमा नहीं)	संविधान में समय-सीमा नहीं

Aspect	President (Parliamentary Bill)	Governor (State Bill)
Ordinary Bill : Options	3 : Assent / Withhold / Return for reconsideration	4 : Assent / Withhold / Return / Reserve for the President
On being passed again	Assent is mandatory (suspensive veto)	Assent is mandatory (suspensive veto)
Money Bill : Options	2 : Assent / Withhold (cannot return)	3 : Assent / Withhold / Reserve for the President (cannot return)
Money Bill : Practice	Generally gives assent	Generally gives assent
Reserved Bill (with the President)	–	Non-money: Assent / Withhold / Direct the Governor to return (6 months); Money: Assent / Withhold
Pocket (Zero) Veto	Yes (no time limit in the Constitution)	No time limit in the Constitution

5) राज्यपाल के विवेकाधिकार (Discretionary Powers) → अनुच्छेद 163

संवैधानिक विवेकाधिकार (Constitutional Discretion)

❑ अनुच्छेद 200 → यदि विधेयक राज्य उच्च न्यायालय (High Court) की शक्तियों को कम करता है, तो इसे राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना बाध्यकारी है।

- ✓ संपत्ति का अनिवार्य अर्जन (अनुच्छेद 31A)
- ✓ समवर्ती सूची और केंद्रीय कानून से टकराव (अनुच्छेद 254(2))
- ✓ 360(4) : यदि देश में वित्तीय आपातकाल लागू हो, तो राष्ट्रपति के निर्देशानुसार राज्य के सभी धन विधेयक और वित्तीय विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित।

❑ अनुच्छेद 356 → यदि राज्यपाल को यह विश्वास हो जाता है कि राज्य सरकार संविधान के विभिन्न प्रावधानों के अनुसार कार्य नहीं चला पा रही है, तो वे राष्ट्रपति को इसकी रिपोर्ट भेज सकते हैं।

❑ 239 (2) → जब वह केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक के रूप में काम करता है, तो वह सीधे राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है।

❑ छठी अनुसूची (असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम) की सरकारों द्वारा स्वायत्त जनजातीय जिला परिषदों को खनिज अन्वेषण लाइसेंस की रॉयल्टी के रूप में देय राशि का निर्धारण

5) Discretionary Powers of the Governor → Article 163

Constitutional Discretion

- ❑ **Article 200** → If a Bill reduces the powers of the State High Court, reserving it for the President is mandatory
 - ✓ Compulsory acquisition of property (Article 31A)
 - ✓ Conflict with the Concurrent List and Central law (Article 254(2))
 - ✓ 360(4): If a Financial Emergency is in force in the country, all Money Bills and Financial Bills of the State are reserved for the President's consideration, as directed by the President.
- ❑ **Article 356** → If the Governor is satisfied that the State Government cannot be carried on in accordance with the provisions of the Constitution, he can send a report to the President
- ❑ **239 (2)** → When he functions as the Administrator of a Union Territory, he acts directly as the representative of the President.
- ❑ Determination of the amount payable by the Governments (Sixth Schedule: Assam, Meghalaya, Tripura, Mizoram) to autonomous tribal District Councils as royalty from mineral exploration licences

परिस्थितिजन्य विवेकाधिकार (Situational Discretion)

- ❑ विधानसभा में किसी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने पर, या कार्यकाल के दौरान CM की अचानक मृत्यु और कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी न होने पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति।
- ❑ मंत्रिपरिषद् के अल्पमत में आ जाने पर विधानसभा का विघटन।

परिस्थिति	राज्यपाल की भूमिका
किसी दल या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत न मिले	बहुमत प्राप्त करने में सक्षम नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करना।
सरकार के बहुमत पर वस्तुनिष्ठ आधार पर संदेह हो	विधानसभा में बहुमत परीक्षण कराना।
सरकार सदन का विश्वास खो दे और इस्तीफा न दे	संवैधानिक शर्तों के अधीन मंत्रिपरिषद् को पद से हटाना।
बहुमत खो चुकी सरकार विधानसभा भंग करने की सलाह दे	वैकल्पिक सरकार बनने की संभावना देखकर निर्णय लेना।



रिपोर्ट	कैसे प्रस्तुत की जाती है?	कहाँ रखी जाती है?
अनु. 151(1) – संघ के खाते	राष्ट्रपति	संसद के दोनों सदनों में
अनु. 151(2) – राज्य के खाते	संबंधित राज्यपाल	राज्य विधानमंडल में

Situational Discretion

- ❑ Appointment of the Chief Minister when no party gets a clear majority in the Assembly, or when the CM dies suddenly during the term and there is no clear successor
- ❑ Dissolution of the Legislative Assembly when the Council of Ministers is reduced to a minority

Situation	Role of the Governor
No party or alliance gets a clear majority	Appoint as Chief Minister the leader who is able to command a majority
There is doubt about the government's majority on an objective basis	Have a floor test conducted in the Assembly
The government loses the confidence of the House and does not resign	Dismiss the Council of Ministers, subject to constitutional conditions
A government that has lost its majority advises dissolution of the Assembly	Take a decision after considering the possibility of an alternative government being formed



<u>रिपोर्ट</u>	<u>किसे प्रस्तुत की जाती है?</u>	<u>कहाँ रखी जाती है?</u>
<u>अनु. 151(1) – संघ के खाते</u>	<u>राष्ट्रपति</u>	<u>संसद के दोनों सदनों में</u>
<u>अनु. 151(2) – राज्य के खाते</u>	<u>संबंधित राज्यपाल</u>	<u>राज्य विधानमंडल में</u>

विशेष उत्तरदायित्व (Special Responsibilities)

संविधान के भाग 21 (अनुच्छेद 371) के तहत कुछ राज्यों के राज्यपालों को विशेष उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं। इन मामलों में वे मंत्रिपरिषद् से परामर्श कर सकते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय उनका अपना (Individual judgement) होता है:

महाराष्ट्र	विदर्भ व मराठवाड़ा के लिए पृथक विकास बोर्ड	371(2)
गुजरात	सौराष्ट्र व कच्छ के लिए पृथक विकास बोर्ड	371(2)
नागालैंड	त्वेनसांग जिले में आंतरिक अशांति के चलते कानून-व्यवस्था	371A
असम	जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन	371B / छठी अनुसूची
मणिपुर	पहाड़ी क्षेत्रों का प्रशासन	371C
सिक्किम	जनता के विभिन्न वर्गों के सामाजिक-आर्थिक विकास के साथ शांति	371F
अरुणाचल प्रदेश	कानून एवं व्यवस्था	371H
कर्नाटक	हैदराबाद-कर्नाटक (अब "कल्याण-कर्नाटक") क्षेत्र के लिए पृथक विकास बोर्ड	371J

- "संविधान स्पष्ट रूप से उल्लेख करता है कि कुछ क्षेत्रों में राज्यपाल अपने विवेक से कार्य करता है"
 - ✓ अनु. 163(1), 163(2), 371A, छठी अनुसूची पैरा 9)।
- राज्यपाल के विवेकाधिकार — (1) राष्ट्रपति शासन हेतु रिपोर्ट भेजना ✓ (2) विधेयक राष्ट्रपति हेतु आरक्षित करना ✓

Special Responsibilities

Part XXI (Articles 371–371J) gives Governors of some states special responsibilities. They may consult the Council of Ministers, but decide in their **own individual judgement**:

Maharashtra	Development boards: Vidarbha, Marathwada, rest of Maharashtra	371(2)
Gujarat	Development boards: Saurashtra, Kutch, rest of Gujarat	371(2)
Nagaland	Law and order during internal disturbance in Naga Hills–Tuensang area	371A
Assam	Administration of tribal areas	Sixth Schedule
Manipur	Administration of the hill areas	371C
Sikkim	Peace and equitable social and economic advancement of all sections	371F(g)
Arunachal Pradesh	Law and order	371H
Karnataka	Development board for Hyderabad–Karnataka (now Kalyana–Karnataka)	371J

- "The Constitution expressly states that in certain matters the Governor acts in his discretion"
 - ✓ **(Art. 163(1), 163(2), 371A, Sixth Schedule Para 9)**
- Governor's discretion: (1) report for President's Rule ✓ (2) reserving a bill for the President ✓

राज्यपाल के पास क्या नहीं है

State Governor: powers not available



1 कोई कूटनीतिक शक्ति नहीं



संधि, राजदूत आदि केवल **राष्ट्रपति** के क्षेत्राधिकार में आते हैं।

2 कोई सैन्य शक्ति नहीं



सर्वोच्च सेनापति केवल **राष्ट्रपति** होता है।

3 कोई आपातकालीन शक्ति नहीं



अनु. 352, 356, 360 की उद्घोषणा केवल **राष्ट्रपति** करता है; राज्यपाल केवल अनु. 356 हेतु रिपोर्ट भेज सकता है।

4 संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति नहीं



राज्य विधानमंडल में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है।

5 राज्यसभा की तरह नामांकन की शक्ति नहीं



राज्यपाल केवल विधान परिषद में **1/6 सदस्यों** को नामित करता है; विधानसभा में अब कोई नामांकन नहीं (2020 के बाद)।



निष्कर्ष: राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख है, परंतु कुछ शक्तियाँ केवल **राष्ट्रपति** के पास ही रहती हैं।



What the Governor Does NOT Have

State Governor: powers not available



1 No Diplomatic Power



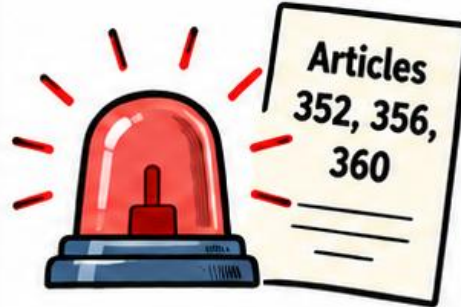
Treaties, ambassadors, etc. fall only within the jurisdiction of the **President**.

2 No Military Power



Only the **President** is the Supreme Commander.

3 No Emergency Power



Proclamations under Arts. 352, 356 and 360 are issued only by the **President**; the Governor can only send a report for Art. 356.

4 No Power to Call a Joint Sitting



There is no provision for a joint sitting in the State Legislature.

5 No Nomination Power like the Rajya Sabha



The Governor nominates only **1/6** of the members to the Legislative Council; there is now no nomination to the Legislative Assembly (after 2020).



Conclusion:

The Governor is the constitutional head of the state, but some powers remain exclusively with the **President**.

